(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी सहाय[illegible]पलब्ध करायी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) शिक्षा विभाग अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना और अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को खोलने/सुदृढ़ करने की योजना।

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित हिन्दी शिक्षकों के पद के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किन्तु यह सहायता केवल एक योजना अवधि के लिए दी जाती है और योजना अवधि समाप्त होने पर इन शिक्षकों को रखने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित हो जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान अहिन्दी भाषी राज्यों को ही दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	(लाख रु.) 1995-96
1.	उड़ीसा	174.15
2.	असम	125.06
3.	मणिपुर	92.95
4.	मिजोरम	15.82
5.	आन्ध्र प्रदेश	2.00
6.	नागालैंड	—
		409.98

2. हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

इस योजना के अंतर्गत, हिन्दी के प्रसार-विकास के विभिन्न कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जैसे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आशुलिपि/टंकण कक्षाएं आयोजित करना, हिन्दी पुस्तकालय खोलना, कार्य विवरणिकाओं/पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि।

सामान्यतया, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन भवनों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार के मामले को छोड़कर, जहां अनुदान अनुमोदित व्यय 60% तक अथवा 50,000/- रुपये, जो भी कम हो सकता है, कुल अनुमोदित व्यय के 75% तक दी जाती है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी में प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी पुस्तकों की भारी खरीद के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान इन योजनाओं पर 249.77 लाख रु. का व्यय है। इसके अतिरिक्त उन हिन्दी लेखकों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे पुरस्कारों की संख्या 19 प्रति वर्ष है और पुरस्कार राशि 15,000/-रुपये प्रति पुस्तक है।

3. अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को हिन्दी का शिक्षण देने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, तमिल, मलयालम, बंगला तथा अंग्रेजी के माध्यम से अहिन्दी भाषी भारतीयों और विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण देने के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी आधारित तथा क्षेत्रीय भाषा आधारित द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोश भी प्रकाशित कर रहा है।

Production of Sugarcane in Bihar

2349. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the production of sugarcane in Bihar during the last three years, yearwise;

(b) whether Government have taken any steps to increase the production and productivity of sugarcane in the State to raise the production of sugar and khandsari; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The production of Sugarcane in Bihar during the last three years i.e. 1993-94, 1994-95 and 1995-96 was 44.0, 56.6 & 56.4 lakh tonnes respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) To increase the production and productivity of sugarcane, a Centrally Sponsored Scheme on Sustainable Development of Sugarcane Based Cropping System (SUBACS) is being implemented in different States including Bihar besides providing market and

price support. Loan is also advanced from Sugar Development Fund to sugar undertakings for development of sugarcane in factory areas.

Pending irrigation projects for clearance

2350. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how many irrigation proposals (Projects) are waiting for clearance;

(b) since when they are pending;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government will prepare a suitable scheme to avoid this delay?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) to (c) List of Irrigation projects waiting for environmental and forestry clearance is given in the Statement. (*See* below).

(d) Projects are normally accorded Environmental clearance within a stipulated time of 120 days after receipt of complete information. The Government constantly monitors all pending proejcts for avoiding delays.

Statement

Projects pending for clearance

S. No.	Name of the Project	Pending since	Reasons for pendency
1	2	3	4
A. Environmental Clearance			
Andhra Pradesh			
1.	Modernisation of Kurnool Cuddapa Canal Irrigation Project	February 1996	Additional information awaited
Haryana			
2.	Sutlej Yamuna Link Canal	September 1996	Under process
Karnataka			
3.	Upper Krishna Project Stage-II	September 1996	-do-
4.	Upper Krishna Stage-I Phase-III	November 1996	-do-
Rajasthan			
5.	Bisalpur Irrigation Project.	January 1994	Additional information awaited
Uttar Pradesh			
6.	Ganga Barrage Project	March 1996	-do-
7.	Agra Barrage Project	April 1996	-do-
8.	Ban Sagar Project	April 1996	-do-
9.	Pre-feasibility report of Karnali Yamuna Link	September 1996	Under process